

इज़राइल की समुद्री डकैती, आतंकवाद, और मदलीन पर बंधक बनाना: अंतरराष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन

9 जून 2025 को, इज़राइली नौसेना ने बेशर्मी से **मदलीन** पर चढ़ाई की, जो कि यूनाइटेड किंगडम के झंडे तले फ्रीडम फ्लोटिला गठबंधन द्वारा संचालित एक जहाज था, जो गाजा से 160 समुद्री मील दूर अंतरराष्ट्रीय जल में था। जहाज पर स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, तुर्की, स्पेन, और नीदरलैंड के 12 कार्यकर्ता सवार थे—जिनमें जलवायु आइकन ग्रेटा थनबर्ग और फ्रांसीसी सांसद रीमा हसन शामिल थीं—जो गाजा में प्रतीकात्मक सहायता पहुंचाने और इज़राइल के अवैध नाकाबंदी को चुनौती देने के लिए एक मानवीय मिशन पर थे। इज़राइल की जबरदस्ती हस्तक्षेप, जिसमें संचार में व्यवधान और एक चिड़चिड़ाने वाले पदार्थ का उपयोग शामिल था, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) के तहत स्पष्ट रूप से समुद्री डकैती, ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस (GTD) मानदंडों के तहत आतंकवाद, और उन देशों के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई है जिनके नागरिकों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा, इन व्यक्तियों की हिरासत, जिसमें एक वर्तमान यूरोपीय संसद सदस्य शामिल है, अंतरराष्ट्रीय बंधक बनाना है, जबकि यूनाइटेड किंगडम का अपने झंडे वाले जहाज की रक्षा करने में विफलता उसकी कानूनी जिम्मेदारियों का शर्मनाक परित्याग है। यह निबंध इज़राइल की कार्रवाइयों को अंतरराष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन मानते हुए उनकी निंदा करता है और जवाबदेही की मांग करता है।

UNCLOS के तहत इज़राइल की कार्रवाइयाँ समुद्री डकैती के रूप में

UNCLOS के अनुच्छेद 101 के अनुसार, समुद्री डकैती को “किसी भी अवैध हिंसा या हिरासत के कार्य, या कोई भी लूटपाट का कार्य, जो निजी उद्देश्यों के लिए निजी जहाज या विमान के चालक दल या यात्रियों द्वारा... खुले समुद्र में किसी अन्य जहाज के खिलाफ किया जाता है” के रूप में परिभाषित किया गया है। इज़राइल का **मदलीन** पर चढ़ाई इस परिभाषा के साथ खतरनाक सटीकता से मेल खाता है। **मदलीन**, यूनाइटेड किंगडम के झंडे तले एक नागरिक जहाज, अंतरराष्ट्रीय जल में था—किसी भी राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर—जब इज़राइली नौसेना बलों ने सशस्त्र हस्तक्षेप किया। यह हिंसक कार्य, जिसमें एक चिड़चिड़ाने वाले पदार्थ का उपयोग और चालक दल की हिरासत शामिल थी, अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत अवैध था, क्योंकि **मदलीन** कोई खतरा नहीं था और एक शांतिपूर्ण मानवीय मिशन में लगा हुआ था।

इज़राइल का गाजा नाकाबंदी लागू करने का दावा इसे UNCLOS से मुक्त नहीं करता। नाकाबंदी स्वयं अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत व्यापक रूप से अवैध मानी जाती है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट गाजा की नागरिक आबादी पर इसके प्रभाव की निंदा करती हैं। भले ही इज़राइल सुरक्षा तर्क का दावा करता हो, UNCLOS का अनुच्छेद 101 सरकारी अभिनेताओं को बिना सहमति या स्पष्ट कानूनी आधार, जैसे कि समुद्री डकैती या मानव तस्करी के सबूत, अंतरराष्ट्रीय जल में विदेशी झंडे वाले जहाजों पर चढ़ने की अनुमति नहीं देता—जो **मदलीन** पर लागू नहीं था। शिशु फार्मूला और चावल ले जा रहे जहाज को रोकने के लिए बल का उपयोग, संचार में व्यवधान और नागरिकों को डराने के साथ, एक विशिष्ट लूटपाट का कार्य है। इसलिए, इज़राइल की कार्रवाइयाँ समुद्री डकैती का गठन करती हैं, जो उसकी नौसेना को कानूनी दायित्व और अंतरराष्ट्रीय निंदा के लिए उजागर करती हैं।

ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस के तहत इज़राइल की कार्रवाइयाँ आतंकवाद के रूप में

मैरीलैंड विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस (GTD) आतंकवाद को “गैर-राज्य या राज्य अभिनेता द्वारा अवैध बल और हिंसा का धमकी या वास्तविक उपयोग, भय, जबरदस्ती या धमकी के माध्यम से राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक या सामाजिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए” के रूप में परिभाषित करता है। इज़राइल का **मदलीन** पर चढ़ाई इस परिभाषा के साथ भयावह रूप से मेल खाता है। एक राज्य अभिनेता के रूप में, इज़राइल ने अवैध बल का उपयोग किया—अंतरराष्ट्रीय जल में यूनाइटेड किंगडम के झंडे तले जहाज पर चढ़ना बिना कानूनी प्राधिकार के—एक राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त

करने के लिए: फ्रीडम फ्लोटिला के गाजा नाकाबंदी को चुनौती देने को दबाना। कार्यकर्ताओं द्वारा रिपोर्ट किए गए एक चिड़चिड़ाने वाले पदार्थ का उपयोग और संचार में व्यवधान, निहत्थे नागरिकों में भय पैदा करने और अनुपालन को मजबूर करने के लिए डिज़ाइन किए गए हिंसक कार्य थे।

GTD मानदंड डराने की मंशा पर जोर देते हैं, और इज़राइल का ग्रेटा थनबर्ग और रीमा हसन जैसे उच्च-प्रोफाइल व्यक्तियों को निशाना बनाना भविष्य के मानवीय मिशनों को रोकने के लिए एक जानबूझकर रणनीति का सुझाव देता है। एक यूरोपीय संसद सदस्य और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कार्यकर्ता को ले जा रहे जहाज पर हमला करके, इज़राइल ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एक धमकी भरा संदेश भेजा: उसकी नीतियों के खिलाफ असहमति को हिंसा का सामना करना पड़ेगा। यह राज्य-प्रायोजित आतंकवादी कार्य, जो खुले समुद्र पर किया गया, अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और 1979 के बंधक लेने के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जैसे ढांचे के तहत अभियोजन की मांग करता है।

यूनाइटेड किंगडम की कानूनी जिम्मेदारी और मदलीन की रक्षा में विफलता

मदलीन के इंडा राज्य के रूप में, यूनाइटेड किंगडम UNCLOS के तहत अपनी अधिकारिता के तहत पंजीकृत जहाजों की रक्षा करने की एक अटल जिम्मेदारी वहन करता है। UNCLOS का अनुच्छेद 94(1) यह अनिवार्य करता है कि इंडा राज्य “प्रशासनिक, तकनीकी और सामाजिक मामलों में अपने इंडे तले नौकायन करने वाले जहाजों पर अपनी अधिकारिता और नियंत्रण को प्रभावी ढंग से लागू करें।” इसमें अंतरराष्ट्रीय जल में यूनाइटेड किंगडम के इंडे तले जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खिलाफ अवैध कार्यों, जैसे समुद्री डकैती या सशस्त्र हमले, का जवाब देना शामिल है। इज़राइल का मदलीन के खिलाफ हस्तक्षेप यूनाइटेड किंगडम के संप्रभु अधिकारों पर एक सीधा हमला था, क्योंकि जहाज का इंडा इसे अंतरराष्ट्रीय जल में विशेष ब्रिटिश अधिकारिता प्रदान करता था।

इस अपमान के सामने यूनाइटेड किंगडम का मौन और निष्क्रियता कर्तव्य का शर्मनाक परित्याग है। चढ़ाई की खबरों के बावजूद, मदलीन या इसके यात्रियों को सुरक्षित करने के लिए तत्काल ब्रिटिश कूटनीतिक या नौसैनिक हस्तक्षेप का कोई सबूत नहीं है। यह विफलता UNCLOS का उल्लंघन करती है और इंडा राज्य प्रणाली की अखंडता को कमजोर करती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि राष्ट्र अपने जहाजों पर अपनी प्राधिकारिता लागू करें। यूनाइटेड किंगडम ने इज़राइल को यूनाइटेड किंगडम के इंडे तले जहाज पर हमला करने की अनुमति देकर अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को धोखा दिया है और बैईमान अभिनेताओं को समुद्री कानून की अवहेलना करने के लिए प्रोत्साहित किया है। ब्रिटिश सरकार को अपनी निष्क्रियता के माध्यम से संलिप्तता के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और मदलीन के चालक दल की तत्काल रिहाई की मांग करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

मदलीन पर मौजूद देशों के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई

इज़राइल का मदलीन पर चढ़ाई और इसके बहुराष्ट्रीय चालक दल की हिरासत—स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, पराग्वे, तुर्की, स्पेन, और नीदरलैंड के नागरिक—इन संप्रभु देशों के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई के समान है। सशस्त्र संघर्ष के अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत, किसी अन्य राज्य के नागरिकों के खिलाफ, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय जल में, सैन्य बल का उपयोग एक युद्धकारी कार्य है। मदलीन के यात्री इज़राइली नागरिक नहीं थे, और उनकी इज़राइली बलों द्वारा हिरासत उनके मूल देशों की संप्रभुता पर एक बाहरी हमला दर्शाती है।

1961 का वियना कन्वेशन डिप्लोमैटिक रिलेशन्स और अंतरराष्ट्रीय प्रथागत कानून यह पुष्टि करते हैं कि विदेश में किसी राज्य के नागरिकों पर हमले को शत्रुतापूर्ण कार्यों के रूप में व्याख्या किया जा सकता है। आठ देशों के नागरिकों को निशाना बनाकर, जिसमें संसदीय उन्मुक्ति वाली एक फ्रांसीसी सांसद शामिल है, इज़राइल ने अभूतपूर्व पैमाने पर एक कूटनीतिक संकट को जन्म दिया है। यह चढ़ाई 2010 के मारी मारमारा घटना की याद दिलाती है, जहां इज़राइल द्वारा तुर्की नागरिकों की हत्या ने तुर्की के साथ संबंध तोड़ दिए। इस बार, यूरोपीय और लैटिन अमेरिकी नागरिकों की भागीदारी दांव को बढ़ा देती है, जिसमें नाटो सहयोगी और यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य शामिल हैं। इज़राइल की मदलीन के खिलाफ लापरवाह आक्रामकता एक वास्तविक युद्ध की घोषणा है, जो अंतरराष्ट्रीय शांति का गंभीर उल्लंघन है जिसे इन देशों को बर्दाशत नहीं करना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय बंधक बनाना, जिसमें एक यूरोपीय संसद सदस्य शामिल है

इज़राइल द्वारा **मदलीन** के 12 यात्रियों की हिरासत, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग और रीमा हसन शामिल हैं, 1979 के बंधक लेने के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के तहत अंतरराष्ट्रीय बंधक बनाना है। अनुच्छेद 1 बंधक बनाना को “कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को जब्त या हिरासत में लेता है और उसे मारने, चोट पहुंचाने या हिरासत में रखने की धमकी देता है ताकि किसी तीसरे पक्ष को... कोई कार्य करने या करने से रोकने के लिए मजबूर किया जाए” के रूप में परिभाषित करता है। इज़राइल द्वारा कार्यकर्ताओं की जब्ती, बिना किसी कानूनी आधार के और निरंतर हिरासत की धमकी के तहत, फ्रीडम फ्लॉटिला और उनके समर्थकों को उनकी मानवीय मिशन को छोड़ने के लिए मजबूर करने का एक स्पष्ट प्रयास है।

रीमा हसन, एक वर्तमान यूरोपीय संसद सदस्य, की हिरासत विशेष रूप से जघन्य है। यूरोपीय सांसद यूरोपीय संघ के विशेषाधिकार और उन्मुक्ति पर प्रोटोकॉल (अनुच्छेद 8) के तहत उन्मुक्ति का आनंद लेते हैं, जो उन्हें उनके कर्तव्यों का पालन करते समय हिरासत से बचाता है। हसन की **मदलीन** मिशन में भागीदारी, जिसमें वह फिलिस्तीनी अधिकारों की वकालत कर रही थी, उनके संसदीय जनादेश के अंतर्गत आता है। इज़राइल का उसे हिरासत में लेने का कार्य यूरोपीय लोकतांत्रिक संस्थानों पर एक सीधा हमला है, जो निर्वाचित अधिकारियों को निशाना बनाने के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस बंधक बनाए जाने की निंदा करनी चाहिए और सभी हिरासत में लिए गए लोगों की तत्काल रिहाई की मांग करनी चाहिए, विशेष रूप से हसन के मामले में।

निष्कर्ष

9 जून 2025 को इज़राइल का **मदलीन** पर चढ़ाई अंतरराष्ट्रीय कानून का एक घोर उल्लंघन है, जो UNCLOS के तहत समुद्री डैकेती, GTD ढांचे के तहत आतंकवाद, और उन देशों के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई का गठन करता है जिनके नागरिक जहाज पर थे। 12 कार्यकर्ताओं की हिरासत, जिसमें एक यूरोपीय संसद सदस्य शामिल है, अंतरराष्ट्रीय बंधक बनाना है, एक अपराध जो त्वरित वैश्विक निंदा की मांग करता है। यूनाइटेड किंगडम की अपने झंडे वाले जहाज की रक्षा करने में विफलता उसकी कानूनी जिम्मेदारियों का शर्मनाक विश्वासघात है, जो समुद्री संप्रभुता के सिद्धांतों को कमज़ोर करता है। इज़राइल की कार्रवाइयाँ केवल उत्तेजक नहीं हैं—वे अंतरराष्ट्रीय मानदंडों, मानवाधिकारों, और कई देशों की संप्रभुता पर एक जानबूझकर हमला हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इज़राइल को जवाबदेह ठहराना चाहिए, **मदलीन** के यात्रियों की रिहाई सुनिश्चित करनी चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी आक्रामक कार्रवाइयाँ कभी दोहराई न जाएँ। इससे कम कुछ भी खुले समुद्र पर अराजकता के सामने आत्मसमर्पण है।